vkj- ,u- vkb- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- iath;u- la[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"kZ % 12 vad % 33 y[kuÅ] eaxyokj 07 fnlEcj ls 13 fnlEcj] 2021 rd i"B&8 ewY; % ,d :i;k

नगालैंड की घटना पर सरकार ने जताया खेद, अमित शाह बोले– मामले की जांच को एसआईटी गठित

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नगालैंड में सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में १४ लोगों की मौत की घटना पर खेद प्रकट करते हुए सोमवार को कहा कि इसकी विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है तथा सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में ऐसे किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। नगालैंड की घटना पर लोकसभा में अपने बयान में अमित शाह ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में उभरती स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और वहां शांति एवं अमन सुनिश्चित करने के लिये जरूरी कदम उठाये गए हैं। उन्होंने कहा, '' भारत सरकार नगालैंड की घटना पर अत्यंत खेद प्रकट करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताती है।'' उन्होंने कहा कि नगालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है जिसे एक महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है। गृह मंत्री ने कहा, ''सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।'' उन्होंने सदन को सूचित किया कि एहतियाती कदम उठाते हुए प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। शाह ने घटना का ब्योरा देते हुए कहा कि ४ दिसंबर को नगालैंड के मौन जिले में भारतीय सेना को उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली और उसके २१वें पैरा कमांडो ने इंतजार किया। उन्होंने कहा कि शाम को एक वाहन उस स्थान पर पहुंचा और सशस्त्र बलों ने उसे रोकने का संकेत दिया लेकिन वह नहीं रूका और आगे निकलने लगा। शाह ने कहा कि इस वाहन में उग्रवादियों के होने के संदेह में इस पर गोलियां चलायी गयीं जिसमें वाहन पर सवार ८ में से छह लोग मारे गए। शाह ने कहा कि बाद में इसे गलत पहचान का मामला पाया गया। सेना इस घटना में घायल दो लोगों को पास के चिकित्सा केंद्र ले गई। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की बटालियन को घेर लिया, दो

वाहनों में आग लगा दी गयी और उन पर हमला किया जिसमें एक सैनिक की जान चली गई और कुछ अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा एवं भीड़ को तितर–बितर करने के लिये बलों ने गोलियां चलाईं और इसमें ७ अन्य लोग मारे गए। शाह ने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि ५ दिसंबर को लगभग २५० लोगों की भीड़ ने असम राइफल्स के भवन पर हमला किया और इस दौरान संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गृह मंत्री ने कहा कि सेना ने भी एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि उन्हें इस घटना पर काफी दुख है और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सेना द्वारा उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। शाह ने कहा कि उन्होंने राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, पूर्वोत्तर प्रभारी को कोहिमा भेजा गया है। गृह मंत्री के बयान से असंतुष्ट होकर कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। विपक्षी दलों का कहना था कि मंत्री के बयान में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का उल्लेख नहीं है और दोषियों पर कार्रवाई के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। इससे पहले लोकसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी), कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, जदयू, राकांपा और बसपा सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने नगालैंड में सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में कम से कम १४ लोगों के मारे जाने का मुद्दा उठाया तथा इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने, मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने तथा गृह मंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। एआईएमआईएम सहित कुछ दलों ने राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को निरस्त करने की मांग की।

प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर दौरा, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ/गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम गोरखपुर पहुंच कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री खाद कारखाना, एम्स आदि योजनाओं की सौगात लेकर मंगलवार दोपहर गोरखपुर आ रहे हैं। योगी उन्हीं की अगवानी के लिए आए हैं। आज शाम यहां आए मुख्यमंत्री ने खाद कारखाना परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ही आमजन की सुरक्षा और सुविधा में किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी कल सात दिसंबर को गोरखपुर एम्स, फर्टिलाइजर कारखाने और आईसीएमआर के जांच केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं। गोरखपुर में दशकों से बंद पड़े फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन अ फ इंडिया के उर्वरक कारखाने को फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने २०१६ में इसका शिलान्यास किया था। हिंदुस्तान उर्वरक के नाम से करीब ६०० एकड़ क्षेत्रफल में बने इस कारखाने को प्रधानमंत्री कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें १२ लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल ही ११२ एकड़ क्षेत्र में एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। २०१६ में उन्होंने इसका शिलान्यास किया

था, यह एम्स कभी बाढ़ और बीमारी के लिए पहचाना जाने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा की नई रोशनी पैदा करेगा। 'नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोल जी' पुणे की तर्ज पर आईसीएमआर का एक क्षेत्रीय केन्द्र भी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल क लेज में बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को इसका भी उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र का शिलान्यास २०१८ में हुआ था। यह न सिर्फ इंसेफलाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया और डेंगू बल्कि कोविड–१९ जैसी महामारी से जुड़े वायरस की भी पहचान करने के साथ–साथ उनके उपचार के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाने इत्यादि का काम भी करेगा।

शिक्षा के बाजारीकरण के लिये पूर्व की सरकारें जिम्मेदार : सतीश द्विवेदी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। जिसके कारण प्रदेश में शिक्षा का बाजारीकरण होता चला गया। डॉ द्विवेदी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्यालय में 'फर्क साफ है' कार्यक्रम के तहत पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व की सरकारों में गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा प्राथमिकता पर नहीं थी। बाजारीकरण की वजह से महंगी होने के कारण शिक्षा गरीब बच्चों से दूर होती चली गयी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने २०१७ से एक मिशन की तरह काम किया और आज की तारीख में गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को स्कूल भेजनें में सक्षम है। सरकार स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति से लेकर यूनिफार्म तक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मंत्री ने कहा कि आज से पांच साल पहले तक प्रदेश में स्कूल के नाम पर टूटे–फूटे जर्जर भवन दिखायी पड़ते थे। उनमें न पीने की पानी की व्यवस्था थी, न बिजली की व्यवस्था थी और न ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी। यूनिफार्म देने के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले ही सामने आते थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने उत्तर प्रदेश को हाईस्कूल व इंटर की

परीक्षाओं में नकल का गढ़ बना दिया था। स्थिति यह थी कि अगर मेधावी छात्र भी अन्य प्रदेश में जाता था तो उसकी मार्कशीट को मान्यता नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में योगी सरकार ने इस छवि को बदला है। आज हमारे विद्यालयों में एक करोड़ ८० लाख से भी ज्यादा छात्र–छात्राएं नामांकित है। पहले की सरकारों में जहां शिक्षक भर्ती का अर्थ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और वर्ग विशेष का लाभ था। वहीं, योगी सरकार में एक लाख २५ हजार शिक्षकों को पूरी पारदर्शिता व बिना किसी भेदभाव के भर्ती किया गया। भाजपा सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प चलाकर एक लाख से ज्यादा स्कूलों का पुनर्रोद्धार किया। स्कूलों में पीने के पानी, बिजली, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर और खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था की। इसके साथ ही भाजपा सरकार ने सभी बच्चों को दो जोड़ी यूनिफार्म के साथ स्वेटर और जूते देने का भी काम किया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में २०१७ से पहले पूरे देश में पांचवें स्थान पर था आज वह दूसरे स्थान पर खड़ा है। आज स्थिति यह है कि लोग अपने बच्चों का नाम निजी विद्यालयों से कटवाकर सरकारी स्कूलों में लिखवा रहे हैं। योगी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में आठ राज्य विश्वविद्यालय बनाए है, ५१ डिग्री कालेजों की स्थापना हुई है, २५० से अधिक इंटर कॉलेज बनाए गए हैं और ३३ मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं।

सम्पादकीय

ओमीक्रोन वैरिएंट चिंताजनक

कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वैरिएंट के बारे में ये खबर राहत देने वाली रही कि शुरुआती संकेतों के मुताबिक इससे संक्रमित व्यक्ति में अधिक गंभीर लक्षण नहीं उभरते हैं। इस बात पर भी बार–बार जोर दिया जा रहा है कि लगभग ४० देशों में इससे संक्रमित मरीजों की पहचान होने के बावजूद अभी तक इससे किसी मौत की खबर नहीं है। अगर इन संकेतों की आगे चल कर पुष्टि होती है, तो बेशक वह बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन इस वैरिएंट के बारे में मिल रहे दूसरे संकेत चिंता बढ़ाने वाले हैं। मसलन, दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये वैरिएंट री–इन्फेक्ट कर रहा है। मतलब, जिन लोगों के शरीर में पहले संक्रमण या टीका लेने की वजह से एंटीब डीज बन चुके हैं, उन्हें भी यह संक्रमित कर रहा है। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है, तो उसका अर्थ होगा कि अभी तक कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में दुनिया में जो प्रगति हुई है, वह बेअसर हो जाएगी। यानी घूम–फिर कर दुनिया वहीं पहुंच जाएगी, जहां वैक्सीन का निर्माण होने के पहले थी। फिर यह खबर भी चिंताजनक है कि ये वैरिएंट बड़े पैमाने बच्चों को संक्रमित कर रहा है। भारत के लिए यह खबर सतर्क करने वाली है कि ओमीक्र न ने एशिया में पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। बीते एक हफ्ते में जापान, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के अलावा भारत में भी इसके संक्रमण के मामले पाए गए। दक्षिण अफ्रीका के ज्यादा जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों का प्रवेश बंद कर देने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में भी नए वैरिएंट का सामुदायिक प्रसार पाया गया है। अमेरिका के भी कम से कम पांच राज्यों में मामले सामने आ चुके हैं। एशिया–प्रशांत के देशों में टीकाकरण की दर में काफी अंतर है और कई जगह स्थिति चिंताजनक है। भारत में पूर्ण टीकाकरण सिर्फ लगभग ३८ प्रतिशत लोगों का हुआ है। इंडोनेशिया में यह आंकड़ा ३५ प्रतिशत है। अमेरिका तक में भी पूरी तरह से टीके की खुराकें ले चुके लोगों की संख्या ६० प्रतिशत से कम ही है। उससे भी अधिक जोखिम की बात यह है कि भारत में लोगों ने एहतियात लगभग छोड़ रखा है। सोशल डिस्टेन्सिंग और मास्क पहनना जैसे उपायों के पालन में बेहद ढिलाई हो चुकी है। इसलिए अब यह आवश्यक है कि एहतियात बरतने में एक बार फिर उस दौर में लौटा जाए, जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी।

एकेटीयू में दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी

लखनऊ। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) का १६वां दीक्षांत समारोह १६ दिसम्बर को आयोजित किया जायेगा। इस मौके पर पहली बार परास्नातक के मेधावियों को भी मेडल दिए जाएंगे। इसके लिए सूची भी जारी कर दी गयी है।

पहली बार मेडल पाने वालों में लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और गाजियाबाद के कॉलेजों के के मेध ावी शामिल हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि एमटेक में अजय कुमार गर्ग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ओंति गर्ग को प्रथम स्थान, सरस्वती हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाराणसी शुभम सहाय व मेरठ इंस्टीट्यूट अ फ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मानसी गुप्ता समान अंकों पर दूसरा स्थान और लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ के आकाश श्रीवास्तव को तीसरा स्थान मिला है। इन्हें पहली बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉज मेडल से नवाजा जाएगा। इसी तरह, एम फार्मा में राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोल जी गाजियाबाद की कामिनी को प्रथम, केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वरदान गुप्ता को दूसरा और इसी संस्थान की सोनिया गोस्वामी को तीसरा स्थान मिला है। इन्हें क्रमश गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉज मेडल दिया जाएगा। ये हैं तैयारियां १६ दिसम्बर को सुबह ११ बजे से होगा कार्यक्रम,स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी मेडल प्रदान किये जाएंगे, मेडल सूची विश्वविद्यालय की ओर से जारी हो चुकी है ८ स्वर्ण, ४ रजत, ४ कांस्य पदक प्रदान किए जाएंगे, एक कुलाधि पति स्वर्ण पदक, एक कमल रानी मेमोरियल अवार्ड (पदक),१६ स्वर्ण, १६ रजत एवं १६ कांस्य पदक प्रदान किये जायेंगे,घटक व शैक्षिक स्वायत्तशासी संस्थानों में ६ स्वर्ण, ६ रजत, ६ कांस्य पदक प्रदान किए जाएंगे।

१५ दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, इन अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर

लखनऊ। आने वाली १५ दिसंबर यानी बुधवार से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव २०२२ को मद्दे नजर रखते हुए योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट लाने के बजाय ४ महीने का लेखानुदान इस सत्र में पास कराएगी। बता दें, वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट भी लाया जा सकता है। मौजूदा १७ वी विधानसभा का यह संभवत आखिरी सत्र है। इसमें सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है। अभी सत्र का कार्यक्रम तय होना है। इसी सत्र के बीच योगी सरकार की कैबिनेट बैठक वाराणसी में १६ दिसंबर को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के इतिहास में मंदिर में कैबिनेट बैठक कर नया इतिहास रचाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर क रीडोर के लोकार्पण की तैयारियां व अन्य योजनाओं की समीक्षा के लिए

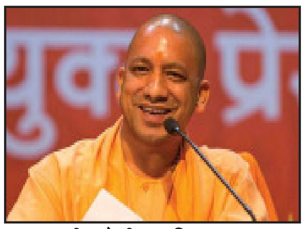

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां कई दिन प्रवास भी करेंगे। वि ानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश सरकार ने लेखानुदान तैयार भी कर लिया है। जुलाई तक के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले लेखानुदान का आकार करीब पौने दो लाख करोड़ का हो सकता है। सरकार चालू वित्तीय वर्ष २०२१ व २०२२ के लिए दूसरा अनुपूरक बजट भी ला सकती है। लेखानुदान के तहत नए वित्तीय वर्ष में जुलाई माह तक के लिए जरूरी खर्चों के लिए बजट का प्रारूप तैयार कर लिया है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक सरकार लेखानुदान इसी १५ दिसंबर को सदन में प्रस्तुत कर सकती है। अनुपूरक के माध यम से एक्सप्रेस वे और जेवर एयरपोर्ट के लिए और धनराशि का आवंटन होने की भी संभावना है। मथुरा के पर्यटन व धार्मिक विकास के मध्य में भी सरकार कोई नई घोषणा कर सकती है। हाल के दिनों में राजनीति हल्के में काशी, अयोध्या के बाद मथुरा की चर्चाएं होने से मथुरा के लिए अनुपूरक से कुछ खास देने का इंतजाम करने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्क लरशिप के मद में भी और बजट का इंतजाम अनुपूरक के माध यम से किए जाने की उम्मीद है।

ओमिक्रॉन को लेकर सरकार सतर्क, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिया जा रहा जोर

लखनऊ। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने के बाद जहां एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार सीमाओं पर सतर्कता बरत रही है तो वहीं ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। नए वैरिएंट ओमिक्र न को लेकर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में सर्तकता सावधानी से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच के अलावा हर एक पॉजिटिव मरीज की जीनोम परीक्षण कराया जा रहा है। प्रदेशवासियों को इस नए वैरिएंट के प्रकोप से बचाने के लिए युद्ध स्थ्तर पर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दे रही है। ओमीक्रान से निपटने के लिए चिकित्सीय व्यवस्थाओं को तेजी से बेहतर किया जा रहा है। प्रदेश के सीएचसी–पीएचसी में १६ हजार बेड और मेडिकल कॉलेजों में ५५

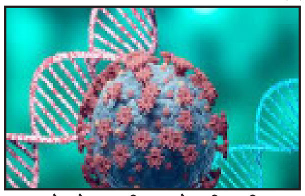

हजारों बेड की बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने स्वच्छता, कोविड प्रोटोकॉल, फोकस टेसटिंग, टीकाकरण, सर्विलांस, सैनिटा इजेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में १०० बेड वाले पीकू नीकू, ८५५ सीएचसी में ५० और ३०११ पीएचसी में १० नए बेड की व्यवस्था की जा रही है। सीएम ने आला अधिकारियों को नए वैरिएंट को लेकर अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ऑक्सीजन, बेड, लैब जैसी व्यवस्थाओं पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। सीएम के आदेश के बाद प्रदेश में एक ओर डेली मॉनीटरिंग को बढ़ाने के साथ ही निगरानी समीतियां अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। विदेश से आने वाले सभी यात्री की आरटीपीसीआर जांच कराने के साथ ही हर एक पॉजिटिव मरीज की जीनोम सीक्वेंसी की जा रही है।

भाजपा की संविधान में आस्था नहीं : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की थी और लोकतंत्र को प्रतिष्ठा दी थी, आज उस पर खतरा मंडरा रहा है। भाजपा का न तो लोकतंत्र में विश्वास है और नहीं संविधान में आस्था है। भाजपा संविधान और उसमें उल्लिखित संस्थाओं को भी कमजोर करना चाहती है। डॉ. आंबेडकर और डॉ. लोहिया मिलकर समाज को नई दिशा देना चाहते थे। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आंबेडकर वादियों और समाजवादियों को मिलकर सत्ता परिवर्तन कर नया भारत बनाना है। यह विचार अखिलेश यादव ने सोमवार को सपा मुख्यालय के डॉ. लोहिया सभागार में डॉ. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के ६६वें परिनिर्वाण दिवस पर व्यक्त किए। उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे विधि विशेषज्ञ के साथ अर्थशास्त्री

और समाजशास्त्री भी थे। दुनिया भर में बाबा साहेब का सम्मान है। उन्होंने अस्पृश्यता को अमानवीय करार देते हुए वंचित दलित समाज का स्वाभिमान जगाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी तथा शिक्षित बनाने पर बल दिया। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा। इसमें मांग की गई है कि प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराये जाए। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में भाजपा सरकार चुनाव प्रभावित करने के लिए षडयंत्र रच रही है। उसके मंत्री–विधायक, नेता, कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ा रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोमवार को आजमगढ़ में लालगंज तथा सदर लोकसभा क्षेत्र में दो सभाएं थी, मुख्यमंत्री की दोनों सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए आजमगढ़ परिवहन निगम की बसों से लोगों को सभा स्थल तक पहुंचाया गया, जिसके कारण सैकड़ो यात्रियो को परेशानी हुई और गैर सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय के वाहनों को जबरन भीड़ जुटाने में लगाया गया।

पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व आईपीएस समेत कई दलों के नेता भाजपा में शामिल

लखनऊ। प्रदेश में दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री किरण आरसी जाटव, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी मनोज झा और कवि सौरभ सुमन सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने सोमवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रदेश भाजपा की सदस्यता समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उपस्थिति में ये नेता भाजपा में शामिल हुए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व अधिकारियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में बसपा के पूर्व प्रत्याशी अभिराम दारा सिंह, कांग्रेस के

रामदास बहेलिया, सिधौली से सपा के ब्लॉक प्रमुख राम बक्श रावत, आगरा से महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शबाना खंडेलवाल, कांग्रेस के राजेश सिंह और प्रसपा की मनीषा सिंह सहित अन्य लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अयोध्या में विवादित ढांचे की बरसी पर सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सवालिया लहजे में कहा कि योगी सरकार की हर उपलब्धि को अपने कार्यकाल का बताने वाले अखिलेश यादव अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने का श्रेय लेना चाहेंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हर बात का श्रेय लेने वाले अखिलेश, क्या आप अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने का श्रेय नहीं लेंगे।

नेत्रहीन को भी चश्मदीद बना देती है बाबा की पुलिसः संजय सिंह

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने मेरठ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुये तंज कसा कि ये बाबा (योगी आदित्यनाथ) की पुलिस है जो नेत्रहीन को भी चश्मदीद बना देती है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मेरठ में एक मीट कारोबारी को जानलेवा हमले के मामले में फंसाते हुए वहां की लिसाड़ी गेट पुलिस ने ना सिर्फ फर्जी मुकदमा दर्ज किया। बल्कि नेत्रहीन को चश्मदीद बनाकर उसके बयान भी दर्ज कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया " ये बाबा की पुलिस है, नेत्रहीन को भी चश्मदीद बना देती है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले में विधि प्रकोष्ठ के साथियों से चर्चा के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पीड़ित को इंसाफ दिलाने के साथ

दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। नगर निगम के अफसर न्यायालय के आदेश को भी नहीं मानते हैं। शासन के आदेश पर नगर निगम में नियमित किए गए कर्मचारियों को अधिकारियों ने मनमानी कर हटा दिया है। यह बातें नगर निगम में बरसों से संविदा पर कार्यरत व हाल ही में हटाए गए २१ कर्मचारियों ने मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान कही है। सोमवार को मार्ग प्रकाश विभाग में संविदा पर कार्यरत लगभग ६५ संविदा कर्मचारी नगर आयुक्त को ज्ञापन देने नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे। कर्मचारियों का कहना है कि १६६७ से नगर निगम में संविदा पर कार्य कर रहे हैं। वेतन भी उन्हें सीधे नगर निगम से मिल रहा है। संविदा कर्मचारी हसन जिया ने बताया कि २०१२, २०१६ और २०१८ में हमें नगर निगम ने निकाल दिया था।

खाद दो वरना यूपी छोड़ों' नारे के साथ कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को 'खाद दो वरना यूपी छोड़ों' नारे के साथ राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसानों की आय दुगना करने का जुमला बोलकर भाजपा सत्ता में आयी थी। पर आज पूरे प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से त्राहि–त्राहि कर रही है। योगी सरकार विज्ञापनों में चेहरा चमका रही है, लेकिन किसानों के खेत खाद जैसी बुनियादी चीज को तरस रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि खाद की समस्या को लेकर प्रदेश के संपूर्ण जिलों, तहसीलों, ब्लॉकों में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में खाद की दुकानों के बाहर लंबी–लंबी लाइन लगी हुई हैं। लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही है। कई गुना ज्यादा दाम पर ब्लैक में किसान खाद खरीदने को मजबूर हैं। डीजल की बढ़ी कीमत ने वैसे ही किसानों की लागत बढ़ा दी है। अब योगी सरकार के कुशासन की वजह से खाद भी

किसानों को रुला रही है। बुंदेलखंड में पिछले दिनों खाद की लाइन में खड़े–खड़े किसान की मौत हुई जो सरकारी तंत्र की हकीकत बयान करता है। लल्लू ने कहा कि योगी सरकार में सबसे ज्यादा छल अन्नदाता के साथ ही हुआ। इसकी शुरूआत तथाकथित कर्जमाफी योजना से शुरू हुई। जिसमें तमाम किन्तु, परन्तु के बाद किसी का एक रुपया, तीस पैसा, पैंसठ पैसा, तीन रुपया का कर्ज माफ हुआ जो किसी मजाक से कम नहीं है। हजारों लाखों के बकायेदार किसान मानसिक तनाव झेल रहे थे। आत्महत्या करने को मजबूर थे, उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आय दोगुना करने की घोषणा करने वाली बीजेपी सरकार इस बात का जवाब दे कि २०१७ से किसानों की लागत लगभग चार गुना से अधिक कैसे हो गयी और इसका जिम्मेदार कौन है। खेती में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला डीजल के दाम दोगुने से ज्यादा हो गया है। खाद की कीमत दोगुने से ज्यादा हो गयी है। नतीजा ये है कि आय तो दोगुनी नहीं हुई, लागत जरूर दोगुनी हो गयी।

मेरठ में कल की रैली से होगा सपा-रालोद गठबंधन के चुनाव प्रचार का आगाज

लखनऊ। सपा और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के बीच चुनावी गठबंधन पर दोनों दलों के नेतृत्व की मुहर लगने के बाद मंगलवार को मेरठ में होने वाली सपा रालोद संयुक्त रैली से गठबंधन के चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरूआत हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी मंगलवार को दोपहर १२ बजे मेरठ में गठबंधन के बैनर तले पहली संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। दोनों दलों की ओर से इसे गठबंधन के साझा चुनाव अभियान के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। सपा और रालोद ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मजबूत किले में सेंधमारी के प्रयोग को सफल बनाने को गठबंधन की मूल वजह बताया है। यह बात दीगर है कि रालोद और सपा के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर बंटवारे का पेंच अभी भी फंसा है। किंतु सपा रालोद गठबंधन की सच्चाई को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिये मेरठ में साझा रैली आयोजित की गयी है। इस बीच रालोद प्रमुख जयंत ने भी सोमवार को दिल्ली में दिये अपने एक बयान में सपा के साथ चुनावी गठबंधन पर पक्की मुहर लगने का स्पष्ट संदेश दिया है। जयंत ने कहा कि सपा–रालोद के गठबंधन की औपचारिक घोषणा पिछले दिनों लखनऊ में अखिलेश से मुलाकात के साथ ही हो गयी थी। उन्होंने भाजपा के साथ भी गठबंधन को लेकर रालोद की बातचीत जारी रहने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुये कहा, "अखिलेश से दोस्ती पक्की है। जयंत ने कहा, "हमारी गाड़ी में यूटर्न का गियर ही नहीं है। अखिलेश से दोस्ती पक्की है। यूटर्न लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इधर, मेरठ में सपा रालोद गठबंधन की पहली रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिये दोनों दलों के नेता शिद्दत से जुटे हैं। सपा के एक नेता ने बताया कि रैली की तैयारियां पूरी हो गयी हैं।

शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा- दोषी कितना भी ताकतवर हो BJP सरकार में कार्रवाई तय

लखनऊ। राजधानी में सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने जल्द ही यूपीटीईटी की परीक्षा कराई जाएगी। एक महीने का वक्त दिया गया है। इसी के अंदर परीक्षा होगी। साथ ही कहा कि टीईटी की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सचिव संजय उपाध्याय दी गई थी। वहीं, उनपर लगे आरोपों के आधार पर कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार में हमेशा से निष्पक्ष काम हुआ है। आरोप चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सतीश द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यूपी पहले पायदान पर है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि योगी सरकार में अ परेशन कायाकल्प में सवा लाख विद्यालय बनाए गए हैं। एक करोड़ १६ लाख बच्चे थे, अब १ करोड़ ८० लाख हैं। भाजपा कार्यकाल में हम शिक्षा के क्षेत्र में पहले पायदान पर खड़े हैं। ५१ डिग्री क लेज बनाए गए हैं। आगे भी विकास पर ही काम किया जा रहा है।

यूपी में प्रभावी पैरवी से ३१ अभियुक्तों को मिला मृत्यु दण्ड

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल के दौरान अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी के जरिये ३१ अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। जबकि ६६५ को उम्रकैद हुयी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान व न्याय के लिये तीन चरणों में चलाये गये प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति अभियान के तहत १७ अक्टूबर २०२० से अक्टूबर २०२१ तक में अपराधियों को सजा दिलाये जाने के सार्थक नतीजे सामने आये है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी के माध्यम से कुल ३१ अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। जबकि ६६५ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के दौरान विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में १३१५ अभियुक्तों को १० वर्ष व १० वर्ष से अधिक की सजा कराने में सफलता मिली है। इसी प्रकार २५५३ अभियुक्तों को १० वर्ष से कम की सजा भी दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा ५०३ अभियुक्तों को जुर्माने से दण्डित कराया गया। साथ ही १८६८१ अभियुक्तों की जमानतें खारिज करायी गयी है।

मोदी और पुतिन की मुलाकात, PM बोले- चुनौतियों के बावजूद रिश्ते और भी मजबूत हुए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत

और रूस के द्विपक्षीय संबंधों और सामरिक भागीदारी पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सामरिक भागीदारी में कोई बदलाव नहीं आया है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दीर्घकालिक दृष्टि अपना रहे हैं। हमने २०२५ तक ३० बिलियन डॉलर ट्रेड और ५० बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है। मोदी और पुतिन २१वें वार्षिक भारत–रूस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी ने कहा कि २०२१ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस वर्ष हमारे १६७१ की ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के पांच दशक और हमारी सामरिक भागीदारी के २ दशक पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच हुए विभिन्न समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कोर डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। वहीं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम सहयोगी हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर साथ काम कर रहे हैं जिसमें ऊर्जा क्षेत्र, अंतरिक्ष सहित उच्च तकनीक शामिल हैं। आज हमने यहां जिन प्रोग्राम पर बात की है उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि मुझे भारत का दौरा करके बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में १७ः की गिरावट हुई थी परन्तु इस साल पहले ६ महीनों में ट्रेड में ३८ः की बढ़ोतरी देखी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार की एम.एस.एम.ई. नीति के अन्तर्गत लाखों उद्यम स्थापित, करोड़ों लोगों को मिला रोजगार

लखनऊ। किसी भी देश के विकास के लिए सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम रीढ़ का कार्य करती है। समाज से व्यक्तियों की कई प्रकार की भौतिक खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उनकी पूर्ति समाज में प्रचलित कुटीर उद्योगों एवं एम.एस.एम.ई. उद्यमों से ही होती है। छोटे उद्यमों के विकास से समाज के परम्परागत कौशल और कला को सजोये रखने में मदद मिलती है, वही उद्यम में लगे लोगों को रोजगार मिलता रहता है। इन उद्यमों से प्रदेश और देश की संसेति को बढ़ावा मिलता है। साथ ही प्रदेश, देश की आर्थिक उन्नति में सहायक होते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के परम्परागत उद्यमों, कारीगरी आदि को बढ़ावा देते हुए नये उद्यमों के स्थापना हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास पर विशेष बल दिया है। इसके विकास के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण वितरित करते हुए उद्यम स्थापित कराकर लोगों को रोजगार दिया गया है।विगत वर्षों में बैंकों के माध्यम से प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को बढ़–चढ़कर ऋण वितरण किया गया। जहां वर्ष २०१६–१७ में केवल रू० २८,१३६ करोड़ का ऋण वितरण एमएसएमई इकाइयों को किया गया था, वहीं वर्ष २०२०–२१ में रू० ७३,७६५ करोड़ का ऋण वितरण किया गया जो विगत ०४ वर्षों में २.५ गुना से अधिक की वृद्धि को दर्शाता हैं। प्रदेश में वर्ष २०२०–२१ की अधिकांश अवधि में प्रदेश में ल कडाउन लागू होने के बावजूद भी यह वृद्धि दर्ज की गयी है। वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गतविगतवर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वितरण की स्थिति बड़ी सफल रही है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष २०१७–१८ में ४६,५६४.०० करोड़ रूपये,वर्ष २०१८–१६ में ५७,८०६.०० करोड़ रूपये, वर्ष २०१६–२० में

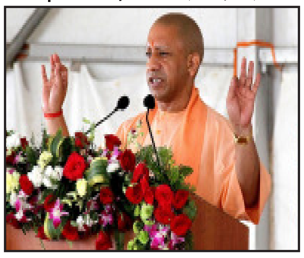

७१,०८०.०० करोड़ रूपये,व वर्ष २०२०–२१ में ७३,७६५.०० करोड़ रुपये ऋण वितरित किया गया। चालू वर्ष में भी लाखों लाभार्थियों को करोड़ों रूपये का ऋण वितरित किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष २०२०–२१ में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बैंको द्वारा प्रदेश में ३४,८०,५६६ नई एमएसएमई इकाईयों को ऋण वितरण किया गया, जिसके माध्यम से लगभग ६३ लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। इस प्रकार वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में लगभग ८० लाख एमएसएमई इकाईयों को ऋण उपलब्ध कराते हुए १.५० करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गए हैं। प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में एम.एस.एम.ई. ईकाइयों की स्थापना कराकर करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर देना सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

दहेज एक सामाजिक बुराई, लेकिन बदलाव समाज के भीतर से आना चाहिए : शीर्ष अदालत

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दहेज एक सामाजिक बुराई है और इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बदलाव समाज के भीतर से आना चाहिए कि परिवार में शामिल होने वाली महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और लोग उसके प्रति कितना सम्मान दिखाते हैं। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर याचिका को विधि आयोग के पास भेज दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद ३२ के तहत उस तरह का कोई उपाय इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, जिसमें अनिवार्य रूप से विधायी सुधारों की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा, ''इस विषय पर मौजूदा कानून के तहत किये जाने वाले उपायों पर विचार करने को लेकर बातचीत शुरू की जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में हमारा मानना है कि यदि भारतीय विधि आयोग इस मुद्दे पर अपने सभी ष्टिकोणों पर विचार करे, तो यह उचित होगा। याचिकाकर्ता विधि आयोग को सहयोग करने की दृष्टि से अनुसंधान और सभी प्रासंगिक पहलुओं पर एक नोट प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।'' पीठ ने आगे कहा, ''कानून में सुधार एक आवश्यकता है, लेकिन समाज के भीतर से एक बदलाव जरूरी होगा कि हम एक महिला के साथ कैसा

व्यवहार करते हैं, समाज उस महिला को कितना सम्मान देता है, जो हमारे परिवार में आती है, एक महिला का सामाजिक जीवन कैसे बदलता है। यह एक संस्था के रूप में विवाह के सामाजिक बुनियादी मूल्य से संबंधित है। यह एक सामाजिक परिवर्तन के बारे में है, जिसके बारे में सुधारकों ने लिखा है और ऐसा करना जारी रखे हुए हैं।' पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम की तरह ही इस याचिका में दहेज–निषेध अधिकारियों को नामित करने के लिए प्रार्थना की गई है, लेकिन यह अदालत ऐसा नहीं कर सकती। पीठ याचिकाकर्ता साबू सेबेस्टियन और अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में उठाये गये सभी मामले विधायिका के संज्ञान में हैं और केवल वही मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है। न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि नोटिस से कुछ भी नहीं निकलेगा और कानून आयोग सुझावों पर गौर कर सकता है और कानून को मजबूत करने के लिए सरकार को उचित सिफारिशें दे सकता है। न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा ''हम आपको बता रहे हैं कि बेहतर विकल्प क्या है। लोगों को इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। नोटिस जारी होने के बाद आप अदालतों में समय बर्बाद कर रहे होंगे।'' उन्होंने कहा कि विधि आयोग का सहारा कम से कम सुधारों की प्रक्रिया को गति देगा।

पहले चर्चा की मांग, फिर हंगामा..... निर्मला सीतारमण बोलीं- यह विपक्ष का दिखावा है।

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि विपक्षी सदस्य पहले चर्चा की मांग करते हैं फिर सरकार के तैयार होने के बावजूद चर्चा नहीं करते और फिर सरकार पर ही चर्चा से भागने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा ''पहले चर्चा की मांग, फिर हंगामा... यह विपक्ष का दिखावा है।'' यह टिप्पणी वित्त मंत्री ने उच्च सदन में आज उस वक्त की जब ''पेट्रोलियम उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं के दाम में वृद्धि की वजह से देश में उत्पन्न हालात'' पर नियत अल्पकालिक चर्चा विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से शुरू नहीं हो पाई। विपक्षी सदस्य १२ निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। सदन में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ''यह विषय उन्होंने (विपक्ष ने) तय किया था। विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता था और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। वे लोकतंत्र की बात करते हैं और हम उनके विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। क्या यह लोकतंत्र और सदन की भावना नहीं है ?'' उन्होंने कहा ''हम चर्चा

से भाग नहीं रहे हैं। विषय तय कर वह (विपक्ष) चर्चा नहीं कर रहे हैं, और फिर हम पर आरोप लगाया जाता है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। हम चर्चा चाहते हैं, महंगाई पर चर्चा चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं। पहले चर्चा की मांग, फिर हंगामा..... यह विपक्ष का दिखावा है।'' वित्त मंत्री का इशारा आसन के समक्ष आ कर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों की ओर था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ शिक्षण संस्थान बंद करने का आदेश, मचा बवाल

जयपुर। कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान में सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थांनों को बंद करने का एक फर्जी आदेश सोमवार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, गृह विभाग ने इस तरह का कोई आदेश जारी करने का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पत्र को लेकर विशेषकर अभिभावकों व विद्यार्थियों में खूब चर्चा रही। इस कथित आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य के सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छह दिसंबर से अगले आदेश तक बंद किए जाते हैं। गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित आदेश फर्जी है क्योंकि वर्तमान गृह सचिव सुरेश गुप्ता हैं जबकि उक्त आदेश पर एनएल मीणा के हस्ताक्षर हैं।

पीएम स्वनिधि योजनाः सड़क पटरी कारोबारियों के लिए उम्मीद की एक किरण

सुमन गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार

कोरोना महामारी के कारण लगाये गए लॉकडाउन से आम लोगों का जीवन अस्त–व्यस्त हो गया था। सड़कों पर सब्जी, फल, खाने–पीने के सामानों का खोमचा, रेहड़ी, ठेला आदि लगाने वाले छोटे मोटे कारोबारी घरों के अन्दर बैठ चुके थे। महामारी के कारण न रेहड़ी लगाने वाले सड़कों पर थे न उन पर बिकने वाले सामानों के खरीदार जब ल कडाउन खुला तो उनके पास पैसे भी नहीं थे किवे अपने कारोबार को शुरू कर सकते। बैकों के कर्ज हैसियतवालों को मिलते हैं ऐसे में इन लोगों के समक्ष जीविकोपार्जन की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। बहुत से कारोबारियों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि यदि उन्हें सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं से पका हुआ भोजन और सूखा राशन न मिलता तो वे काल के गाल में समा गए होते। लम्बे लॉकडाउन, कोरोना के संक्रमण के भय के कारण खाने पीने की वस्तुओं, बाहर के सामानों की खरीद फरोख्त से परहेज करने के कारण भी इन लोगों की रीढ़ टूट चुकी थी। ऐसे में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली, फलवाले जैसे छोटी पूंजी पर जीविकोपार्जन करने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लांच की गई। जिससे असंगठित क्षेत्र में रोजमर्रा रेहड़ी पटरी पर दूकान लगाकर जीवन गुजारने वाले ऐसे लोग पुनः अपना व्यापार शुरू कर सकें। इस कर्ज की ,खासियत थी कि यदि यह एक वर्ष के अन्दर चुकता करना होगा तभी उन्हें अगला कर्ज मिल सकेगा। यही नहीं कर्ज के तहत प्रोत्साहन स्कीम का लाभ भी उन्हें मिलेगा जब वे नियमित तौर पर कर्ज अदायगी करते रहें। अब इस

योजना को लागू होने के एक वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में लोगों की जिन्दगी को पटरी पर लाने में यह कितना सहायक सिद्ध हुई है इसमें क्या–क्या कठिनाइयां आ रही हैं इसका मूल्यांकन करने की भी जरूरत है। चूंकि इस कर्ज की प्रेंति बिना किसी गारण्टी के ऋण प्रदान करने की है। इसलिए छोटे कारोबारियों रेहड़ी पटरी पर अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी योजना है। आवास एवं शहरी मंत्रालय की फंडिग के तहत चल रही इस स्कीम के सम्बन्ध में सरकारी बेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार पहले टर्म के कर्ज के लिए ४२,४८ २६३ लोगों के आवेदन पात्रता सूची में पाये गए हैं। ३००६३६५ आवेदनों को मंजूरी दी गई। २६ ६२६२८ लोगों को कर्ज अदायगी का पात्र माना गया। ६७६४६५ आवेदन अपात्र मानते हुए खारिज कर दिए गए। वहीं, दूसरे टर्म के कर्ज के लिए कुल ६६४४० लोगों के आवेदन आये ४१२६३ लोगों को मंजूरी दी गई। इनमें से २६२१४ लोगों कर्ज पाने की पात्रता तक पहुंचे। इस प्रकार देखा जाये तो इस स्कीम का लाभ के लिए अब तक लगभग ४२ लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस स्कीम के तहत लक्ष्य आठ लाख तीस हजार का है। कोरोनाकाल के संकट से छोटे पूंजी पर कारोबार करने वाले कारोबारी बाजार से बढेध दरों पर कर्ज लेकर उसकी अदायगी भी कर पाने में सक्षम नहीं पा रहे थे। बाजार के कर्ज दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने वाले होते हैं। बंद व्यापार को फिर से शुरू करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस योजना से उनके कष्टप्रद जीवन में उम्मीद की एक किरण दिखी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा कि सड़कों पर रेहड़ी ठेला लगाने वाले लोगों को आसानी से कर्ज उपलब्ध हो सके और वह भी बाजार से कम ब्याज दरों बिना गारण्टीवाला हो। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से पहली जून २०२० को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की गई। जिसकी औपचारिक शुरूआत २२ जुलाई से हुई। इस योजना में दस हजार रूपये तक का कर्ज दिया जाता है। यह योजना मुख्यरूप से छोटी पूंजी से सब्जी, फल, फूल व अन्य सामान ठेले पटरी पर लगाकर बेंचने वाले, फेरी वाले अपना कारोबार चलाने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत १० हजार रुपये तक का बिना किसी गारण्टी के या कोई सम्पति गिरवी रखे बिना कर्ज दिया जाता है। राष्ट्रीयेंत बैंकों के अलावा भी अन्य बैंकिंग कारोबारी लिस्टेड संस्थाएं भी यह ऋण दे सकती हैं। जिसका इस्तेमाल स्ट्रीट वेंडर्स अपने पूंजी के तौर पर कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग ५०–६० लाख लोग छोटे–बड़े शहरों महानगरों में असंगठित रूप से जीविकोपार्जन के लिए रोज सड़क पटरी पर कारोबार का कार्य करते हैं। इस तरह से इस योजना से भारत के लगभग ५० लाख रेहड़ी पटरी वाले वेंडर्स को उनके कारोबार में सहायता मिल सके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के प्रावधान किए गए। उनके लिए डिजिटल कार्ड बनाने सर्वे करने की जिम्मेदारी नगर निकायों को दी गई। इस योजना के तहत एक साल में १०,००० रुपये का लोन छोटी पूंजी से कारोबार करने वालों को दिया जाता है जिससे वे अपने कारोबार को चला सकें। बैंको को कर्ज वापसी हो सके इसके लिए इस योजना में एक प्रोत्साहन लाभ भी रखा गया कि यदि कोई इस स्कीम के तहत कर्ज लेकर निर्धारित समय पर कर्ज चुकाता है तो उसे प्रतिवर्ष सात प्रतिशत के हिसाब से ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है। यदि वह व्यक्ति डिजिटल तौर पर लेन–देन करता है तो उसे एक वर्ष में १२०० रूपये कैशबैक का लाभ भी मिल जाता है। यदि नियमित तौर पर कर्ज का भुगतान करता रहे तो उसे फिर कर्ज लेने का पात्र माना जाता है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में ऐसे वेंडरों को लाभ देने की एक सीमा भी तय है। उत्तर प्रदेश में यह सीमा आठ तीस हजार है। नगर निगम, स्थानीय निकायों के अन्तर्गत जो वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए एक बड़ी समस्या है यदि सर्वे में उनका नाम आया है तभी वे इसके पात्र हो सकेंगे। नहीं तो इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे लोग प्रायः सर्वे में छूट जाते हैं और उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरी कठिनाई बैंको से आती है क्योंकि कई बार बैंक उनके भुगतान की स्थिति की जांच करते हैं कि उक्त व्यक्ति ने पहले से तो कोई कर्ज नहीं ले रखा है। इस योजना का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को योजना के कार्यान्वयन का भागीदार बनाया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन देने की शुरुआत २२ जुलाई २०२० में की गयी थी. तब से १६ फरवरी २०२१ तक योजना के तहत लोन लेने के लिए ४२ लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं।

१ जनवरी २०२२ से अपना ही पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, जानें क्यों

लखनऊ। आने वाली १ जनवरी २०२२ से बैंक के ग्राहकों को अधिक शुल्क चुकाना होगा। कई बैंकों ने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव आने वाली १ जनवरी २०२२ से लागू होंगे। इसी तरह पोस्ट अ फिस के अंतर्गत आने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी एटीएम ट्रांजैक्शन व बैंक से निकासी के नियमों में बदलाव किया है। इसके नए नियम भी १ जनवरी से ही लागू होंगे। पोस्ट ऑफिस के पेमेंट बैंक के बारे में आपको बता दें की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी के मुताबिक बेसिक सेविंग अकाउंट पर नकदी निकासी ४ इंजेक्शन तक ही मुफ्त होगी। यानी कि ग्राहक १ महीने में अपनी बेसिक सेविंग अकाउंट से एटीएम या बैंक खाते से चार बार बिना कोई शुल्क चुकाए नकदी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद ट्रांजैक्शन करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। जितना पैसा निकाल रहे हैं उसका ०.५० फीस दी या प्रति ट्रांजैक्शन रू २५ तक भी देने पड़ सकते हैं। रिजर्व बैंक अझूफ इंडिया आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, अब फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट से अधिक पैसा निकालने पर आपको पहले की अपेक्षा अधिक पैसे देने होंगे। अभी फ्री ट्रांजैक्शन के बाद पैसे निकालने पर रू २० का चार्ज लगता है लेकिन आगामी साल २०२२ से २१ का शुल्क लगने लगेगा। आपको बता दें कि या चार्ज एंड फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजेक्शन पर लगेगा। बेसिक सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट फ्री है और इस पर कोई चार्ज नहीं रखा गया है। इस नियम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा किसी और सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसे निकालते हैं तो प्रति महीने रू २५००० तक फ्री है। लेकिन उसके बाद पति ट्रांजैक्शन पर ०.५० फीसदी या न्यूनतम रू २५ प्रति ट्रांजैक्शन तक शुल्क देना पड़ सकता है। कैश डिपॉजिट को लेकर भी नियम में बदलाव किया गया है। बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा किसी अन्य सेविंग या करंट अकाउंट में कैश डिपाजिट करते हैं तो यह प्रति महीने रू १०००० तक फ्री है। लेकिन उससे ज्यादा की राशि जमा करने पर पति ट्रांजैक्शन ०.५० फीसदी या न्यूनतम रू २५ तक चुकाने होंगे। प्राइवेट बैंकों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने सर्विस चार्ज बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सेविंग अकाउंट पर इसका नया नियम एक जनवरी २०२२ से लागू होगा। बैंक में यह भी कहा है कि १ जनवरी से एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज पर भी असर पड़ेगा। एटीएम

ट्रांजेक्शन चार्ज में बदलाव के बाद, १ महीने में पहले पांच लेन देन निशुल्क होंगे, इसके बाद प्रति फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रू २१ तक का शुल्क लिया जाएगा। पांचवी ट्रांजैक्शन के बाद अलग से चार्ज वसूला जाएगा। नियमों में बदलाव के बाद एटीएम लेनदेन शुल्क के रूप में २१ प्रति वित्तीय लेनदेन और ८.५० रुपए प्रति गैर वित्तीय लेनदेन के लिए शुल्क लिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक के ग्राहक १ महीने में पांच जंक्शन मुक्त करने की सुविधा पाते हैं या नियम सभी शहरों के लिए है। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, और हैदराबाद के एटीएम में किए गए पहले तीन लेनदेन प्रतिमा वित्तीय और गैर वित्तीय मुफ्त है। एचडीएफसी बैंक के मुताबिक फ्री लिमिट से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लगेगा। लिमिट पार होने के बाद प्रतिभूति जंक्शन पर रू २१ प्लस टैक्स चुकाना होगा। अगर गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस चेक या स्टेटमेंट निकालना आदि करते हैं तो एचडीएफसी बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम पर ८.५ रुपय अतिरिक्त देने होंगे। या नियम एक जनवरी २०२२ से लागू कर दिया जाएगा। एक्सिस बैंक में भी लगभग यही नियम लागू किया है। एक्सिस बैंक के एटीएम से फ्री लिमिट के अलावा पैसे निकालने पर रू २० प्लस टैक्स चुकाना होता है। वहीं गैर वित्तीय लेनदेन पर या शुल्क रू १० है। गैर वित्तीय लेनदेन के शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन वित्तीय लेनदेन अगर ५ फ्री लिमिट से अधिक करते हैं तो प्रति ट्रांजैक्शन रू २१ प्लस टैक्स चुकाना होगा। एक्सिस बैंक का नया नियम एक जनवरी २०२२ से लागू होगा।

जयराम सिंह इन्टर कॉलेज मे कोरोना वायरस की गाइड लाइन का पालन कर हो रही पढाई

गोला खीरी। एक बार फिर से कोरोना वायरस की दस्तक जारी हो चुकी है जिसके चलते सभी विद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हैं पढ़ाई वर्क क्लास लगाने के आदेश जारी किए गए है। जनक सिंह इंटर क लेज के बघमरा के प्राचार्य अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार व क्लासों में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते काश लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके चलते सभी कालेज के अध्यापक गणों को सख्त हिदायत दी गई है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग के चलते क्लासों में बच्चों की सीटों का संचालन करें। व बिना मास्क किसी भी बच्चे को कालेज परिसर में प्रवेश न दें, वही कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि बिना हाथों को सैनिटाइजर करें कॉलेज के अंदर प्रवेश की आजादी नहीं है, कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि हिंदुस्तान के कुछ प्रदेशों में ओमीक्रान वायरस के मरीजों के मिलने के चलते कालेज प्रशासन तंत्र ने सभी के लिए नियम लागू कर दिए हैं।

फार्मेसिस्टों ने आन्दोलन के द्वितीय चरण में काला फीता बॉधकर की स्वास्थ्य मेले की ड्यूटी

कृष्ण कुमार शुक्ला

लखीमपुर खीरी। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का मन बना चुके डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के समस्त सदस्य और पदाधिकारियों ने मांगे न माने जाने पर स्वास्थ्य मेले में काला फीता बांधकर विरोध जताया।डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद खीरी के फार्मेसिस्टों ने आन्दोलन के प्रथम चरण में दिनांक ०४ दिसम्बर २०२१ को सीएमओ आफिस पर धरना दे कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। आन्दोलन के द्वितीय चरण में दिनांक ०५ दिसम्बर २०२१ को काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य मेले में ड्यूटी की। आज दूसरे चरण के आन्दोलन के दूसरे दिन भी प्रदेश के फार्मेसिस्टों के साथ जनपद खीरी के फार्मेसिस्टों ने भी काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य किया। जिला चिकित्सालय खीरी में डीपीए के अध्यक्ष ड अशोक कुमार कनौजिया की अगुवाई में सभी फार्मेसिस्ट एवं चीफ फार्मेसिस्ट काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संगठन की न्यायोचित मांगों पर जल्द विचार करके शासनादेश जारी नहीं किये जाते हैं तो फार्मेसी संवर्ग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी दिनांक ०६ दिसम्बर २०२१ से प्रातः दो घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे और दिनांक १७ दिसम्बर २०२१ से १६ दिसम्बर २०२१ तक पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। यदि फिर भी सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है तो दिनांक २० दिसम्बर २०२१ से जनपद के समस्त फार्मेसिस्ट और चीफ फार्मेसिस्ट आकस्मिक सेवाएं तथा पोस्ट मार्टम सेवाएं बधित कर दी जायेगी और अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जायेंगे। डीपीए के मन्त्री ड अनिल कुमार ने बताया कि संगठन नहीं चाहता है कि आन्दोलन से जनता को कष्ट हो इसलिए आन्दोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बीस सूत्रीय मांग पत्र पर विचार करके शासनादेश जारी करे जिससे जनमानस के निर्बाध रूप से स्वास्थ सेवाएं मिलती रहें। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हमारी मांगें नहीं मान रही है।

ग्रामीणों ने ६५ वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को किया याद

कृष्ण कुमार शुक्ला

बॉकेगंज खीरी। भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर का ६५ वां महापरिनिर्वाण दिवस सोमवार को दुलारेपुर गांव सहित जगह–जगह भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान लोगों ने उनके चित्र और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। वहीं, सुबह के समय गांव में अंबेडकर अनुयायियों ने एकत्र होकर पुष्प अर्पित किए।इस दौरान दुलारेपुर गांव में मुख्य अतिथि के रूप में आर बी लाल गौतम ने बाबा साहेब के चित्र और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। दीप प्रज्ज्वलन कर त्रिशरण व पंचशील सिद्धांत पर चर्चा की गई। उसे जीवन में अपनाने का संकल्प लिया गया। विकासखंड बांकेगंज के जटपुरा गांव में भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पअर्पित कर उन्हें नमन किया गया। आर.बी.लाल गौतम ने कहा कि सम्मान दिलाने में बाबा साहेब का विशेष योगदान रहा। हमें उनके बताए मार्गो पर चलना चाहिए।इस अवसर पर आर बी लाल गौतम,सरोज देवी, महेंद्र, जितेंद्र कुमार, विनय, संदीप, रंजीत, नीरज कुमारी, गीता देवी, आलोक कुमार गौतम, कौशल्या देवी, आदि लोग मौजूद रहे।

मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से मतदाताओं को बच्चों ने किया जागरूक

कृष्ण कुमार शुक्ला

लखीमपुर खीरी। विकास खंड रमियाबेहड़ में एस डी एम के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर किया प्रतिभाग। "सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो" जैसे नारों के साथ सोमवार को विकास खंड रमियाबेहड़ के ब्ल क संसाधन केंद्र रामियाबेहड़ से एक संयुक्त मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया ।रैली में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, गायत्री विद्या मंदिर इंटर क लेज, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय रमिया बेहड़ के बच्चों ने उत्साह पूर्वक प्रतिभाग किया। रैली का षुभारंभ उप जिला अधिकारी धौरहरा धीरेंद्र सिंह द्वारा किया गया। रैली में तहसीलदार धौरहरा संतोश कुमार षुक्ला,खंड विकास अधिकारी कमल कांत सिंह, एवं खंड शिक्षा अधिकारी रमिया बेहड़ उपेंद्र सिंह ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और बताया सभी छात्र अपने अपने गांव में मतदाताओं को जागरूक करें और बताएं सभी मतदाता अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। बच्चों ने खंड शिक्षा अधिकारी रमिया बेहड़ के कार्यालय से गगनभेदी जागरूकता नारों के साथ रैली का आरंभ किया। यह रैली रमिया बेहड़ बाजार के मुख्य मार्ग से गुजरते हुए ग्रामीण जनता को जागरूक करते हुए पुनः बीआरसी कैंपस पर समाप्त हुई। रैली से पूर्व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियों के मध्य पोस्टर एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उप जिला अधिकारी धीरेंद्र सिंह ने छात्र छात्राओं को बताया किस प्रकार उन्हें अपने माता–पिता व पड़ोसी से वोट देने हेतु अपील करना है। गायत्री विद्या मंदिर इंटर क लेज के छात्र छात्राओं को जो १८ वर्श की आयु पूर्ण कर चुके हो उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम अवष्य जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। खंड विकास अधिकारी कमल कांत सिंह ने सभी अभिभावकों एवं ग्रामीणों से लोकतंत्र के इस चुनाव रूपी महापर्व में बढ़–चढ़कर उत्साह पूर्वक भागीदारी करने को कहा। बी डी ओ और बी ई ओ ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा मतदान हेतु वोटर लिस्ट में नाम अवष्य होना चाहिए। इस दौरान एस डी एम धौरहरा धीरेन्द्र सिंह, तहसीलदार धौरहरा संतोश कुमार षुक्ला,बी डी ओ रमियाबेहड़ कमल कांत सिंह,बी ई ओ रमियाबेहड़ उपेंद्र कुमार सिंह, रंजीत वर्मा, संतोश वर्मा ,पवन वर्मा सहित तमाम कर्मचारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। अंत में खंड शिक्षा अधिकारी उपेंद्र सिंह ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।

सात वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दरिंदगी

लखनऊ। बंथरा इलाके के एक गांव में शादी समारोह से सात साल की बच्ची का अपहरण कर युवक ने उसके साथ दरिंदगी की। विरोध पर जमकर पीटा और मुंह पर टेप चिपका कर खेत में फेंक दिया। बच्ची शुक्रवार सुबह बदहवास हालत में खेत में पड़ी मिली। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पुलिस आरोपित की तलाश में दबिश दे रही है। बंथरा के एक गांव में रहने वाली सात वर्षीय बच्ची के परिवार में गुरुवार को शादी थी। बारात में पड़ोस के गांव का २२ वर्षीय शिवम भी पहुंचा। देर रात घर वाले शादी समारोह में था खाना और डांस चल रहा था। इस बीच मौका पाते ही शिवम, बच्ची को अपने साथ लेकर चला गया। उसने गांव के बाहर खेत में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर उसे पीटा। बच्ची ने जब शोर मचाने की कोशिश की तो उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। वारदात के बाद आरोपित बच्ची को खेत में फेंककर धमकाते हुए भाग निकला। उधर, कई घंटे तक जब बच्ची घर समारोह स्थल और घर के आस पास नहीं दिखी तो परिवारीजन ने खोजबीन शुरू की।इस बीच शुक्रवार सुबह बच्ची खेत में बदहवास हालत में पड़ी मिली। घरवालों ने यह देख बच्ची को उठाया और पुलिस को सूचना दी। बच्ची की हालत नाजुक देख उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बंथरा अजय प्रताप सिंह, एडीसीपी सेंट्रल राघवेंद्र मिश्रा और डीसीपी डा. ख्याति गर्ग पहुंची। मौके की पड़ताल की। इसके बाद समारोह में विडियो रिकार्डिंग कर रहे फोटो ग्राफर के कैमरे से मिली फुटेज बरामद की। फुटेज में शिवम बच्ची को ले जाते दिखा। एडीसीपी ने बताया कि आरोपित की तलाश में चार टीमें गठित की गई हैं। टीमें दबिश दे रही हैं जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अद्भुत क्षेत्र : जीवन से मुक्त क्षेत्र

अमरेन्द्र सहाय अमर

अभी तक यह समझा जाता था कि पृथ्वी के हर कोने पर जीवन मौजूद है. फिर चाहें इंसान के रूप में हो, जीव के रूप में हो या सूक्ष्म जीव के रूप में. हालांकि एक नई रिसर्च में यह बात सामने आई कि इस दुनिया में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ जीवन का कोई लक्षण नही मिलता है य एक नई रिसर्च ने दावा किया है कि अभी तक पूरी पृथ्वी पर जीवन नहीं पहुंचा है. पृथ्वी पर कहीं भी मुट्ठी भर मिट्टी को छानने पर लाखों सूक्ष्य जीव और कीड़े पाए जा सकते हैं चिली में अटाकामा के वीरान रेगिस्तान से लेकर येलोस्टोन ज्वालामुखी तक इस ग्रह पर दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में भी जीवन सांस ले रहा है. लेकिन एक नए अध्ययन ने इन दावों को झुठला दिया है, जो बताता है कि अंटार्कटिका के ट्रांसअंटार्कटिक पहाड़ों के बीच अभी भी जीवन का पहुंचना बाकी है. ब्रिघम यंग

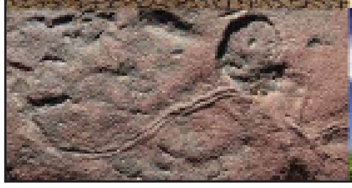

यूनिवर्सिटी यानि बीवाईयू और अमेरिकामें कोलोराडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस सुदूर पर्वत श्रृंखला की यात्रा की. वैज्ञानिकों का मकसद इस बात की खोज करना था कि हजारों सालों में मिट्टी में जीवन कैसे विकसित हुआ है. अपनी यात्रा के दौरान वैज्ञानिक हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने श्कुछ भीश नहीं खोजा. इस रिसर्च का नेतृत्व करने वाले बीईयू जीव विज्ञानी बायरन एडम्स ने कहा कि एक ग्राम मिट्टी में एक अरब तक सेल्स मौजूद हो सकती हैं लेकिन हमें इस मिट्टी में एक भी कोशिका नहीं उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने भी बिना माइक्रोब्स वाली मिट्टी कभी नहीं देखी थी. हमने एक ऐसे वातावरण की खोज की है जहां जीवन मौजूद नहीं है और यह वातावरण पृथ्वी पर खोजा गया है. वैज्ञानिकों ने अपनी खोज को जर्नल अ फ जियोफिजिकल रिसर्च रू बायोजियोसाइंसेज प्रकाशित किया है. इस रिसर्च में साउथ पोल से करीब ३०० मील की दूरी पर शेकलटन ग्लेशियर क्षेत्र से इकट्ठा किए गए २०४ मिट्टी के नमूने शामिल थे, जो पूरी तरह बर्फ से मुक्त थे. जांच में शामिल ज्यादातर मिट्टी में माइक्रोब्स के अलग–अलग मिश्रण पाए गए. हालांकि २० फीसदी मिट्टी पूरी तरह जीवन से मुक्त पाई गई. यह नमूने क्षेत्र के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे शुष्क हिस्सों से लिए गए थे. इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि मिट्टी में किसी भी माइक्रोब्स के लक्षण नही मिले . यहाँ की मिटटी जीवन के लक्षणों से मुक्त थी।

जेठ ने बनाया अश्लील वीडियो और पति ने पीटकर गिराया गर्भ

लखनऊ। तीन तलाक के खिलाफ भले ही सरकार ने सख्त कानून बना दिया हो, लेकिन इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लखनऊ की खदरा निवासी एक महिला ने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पति और जेठ समेत छह लोगों पर मड़ियांव कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरा न करने पर आरोपित महिला को प्रताड़ित कर रहे थे और घर से बाहर निकाल दिया।पीड़िता के मुताबिक जून २०२० में मड़ियांव निवासी जसीम से उनका निकाह हुआ था। आरोप है कि ससुराल में कम दहेज लाने को लेकर ताना सुनाया जाता था। कई बार उसने पति से इस बारे में कहा तो उसने भी ससुराल वालों का ही पक्ष लिया। इससे महिला लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन आरोपित उस पर रहम की जगह क्रूरता दिखा रहे थे।महिला के गर्भवती हो जाने पर पति ने गर्भपात कराने के लिए कहा। इंकार करने पर पति ने उसकी इतनी बेदर्दी से पिटाई किया कि गर्भ गिर गया। इससे महिला की जान पर आफत बन आई। आरोप है कि जब पीड़िता ने थाने में शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने मामूली धाराओं में एफआइआर दर्ज कर उसे वापस भेज दिया। इसके बाद से ससुराल वालों की प्रताड़ना और बढ़ गई।आरोप है कि जेठ ने महिला का नहाते हुए वीडियो बना लिया। पीड़िता सबकुछ सहती रही। इसी बीच २० नवंबर को पति ने पीड़िता से घर जाकर और दहेज लेकर आने के लिए कहा। इंकार करने पर आरोपित ने महिला को तीन तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। मायके वालों ने सुलह समझौते का प्रयास किया, लेकिन आरोपित नहीं माने। इसके बाद पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की।

अवैध कच्ची शराब के साथ युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। गोसाईगंज पुलिस ने एक युवक को अवैध कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार जमा तलाशी के दौरान युवक के पास से १० लीटर अवैध कच्ची शराब पुलिस ने किया बरामद आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक गोसाईगंज पुलिस द्वारा हंसराज पुत्र राजाराम निवासी साठवारा

थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को बरगदहा रोड पर बने मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया जमा तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से १० लीटर अवैध कच्ची शराब पुलिस ने किया बरामद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर गोसाईगंज कोतवाली लेकर आई आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

स्कूल, हास्पिटल और मंदिर के निकट शराब की दुकान पर सरकार से जवाब तलब

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शहर के हरदोई रोड स्थित बालागंज इलाके में स्कूल, हास्पिटल, मंदिर और रिहायशी इलाके से सटकर शराब की दुकान चलाने के मामलों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई १५ दिसंबर तय की है।यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस विवेक वर्मा की पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया। याची का कहना था कि वह बालागंज क्षेत्र मे रहता है। वहां हरि बाजार में शराब की एक दुकान चल रही है जिसके नजदीक ही सेंट जोसेफ स्कूल, जेपीएस चिल्ड्रेन हास्पिटल, पचास साल पुराना एक मंदिर व रिहायशी इलाका पड़ता है। इस इलाके से महिलाएं, बच्चे और बड़ी संख्या में लोग मंदिर आते–जाते हैं जिन्हें शराब की दुकान के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।कहा गया कि दुकान क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति के नाम है। यूपी नंबर एंड लोकेशन आफ एक्साइज शाप रूल्स १६६८ के तहत इस दुकान को यहां नहीं चलाया जा सकता है। याची की मांग थी कि दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाये। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए सरकारी अधिवक्ता को इस प्रकरण पर सरकार से समुचित निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया है कि इस मसले पर क्या किया जा रहा है।

काली फिल्म एवं मोडिफाई साइलेंसर वाली गाड़ियों पर हुई कारवाही

लखीमपुर खीरी।जनपद खीरी में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन खीरी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता एवं चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसका ३० नवंबर २०२१ को पुलिस लाइन में समापन किया गया। जिसके बाद अब जनपद में म डिफाई साइलेंसर काली गाड़ी और काली फिल्म लगाकर चलने वाले लोगों पर कार्यवाही की गई। जिसमें माह दिसंबर में यातायात प्रभारी निर्मलजीत यादव ने आज चौथे दिन मेला मैदान चौराहे पर चेकिंग के दौरान गाड़ियों में काली फिल्म लगाकर चलने वालों और म डिफाई साइलेंसर वाले गाड़ियों को यातायात पुलिस के द्वारा गाड़ियों में काली फिल्म और मॉडिफाई साइलेंसर लगी देखी गई जिस पर टी एस आई ने उन सभी गाड़ियों से काली फिल्म और सेलेंसर को मिस्त्री द्वारा बुलाकर उन गाड़ियों से निकलवाया गया और गाड़ियों पर लगी फिल्म को भी निकलने का काम किया गया। जिसमे टी एस आई निर्मल जीत यादव,राजेश कुमार, सहित मय पुलिस फोर्स मौजूद रहा।

एनएचएम के संविदा कर्मियों की चल रही हड़ताल हुई समाप्त

लखीमपुर खीरी। मीडिया प्रभारी देवनंदन श्रीवास्तव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के आवाहन पर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल दोपहर बाद प्रदेश कार्यकारिणी और एसीएस और एमडी के साथ सार्थक रूप में सामने आई है। जिसके बाद पांच मांगों को माना गया है। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी के आवाहन पर संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मंगलवार से समस्त संविदा कर्मचारी दूनी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य में जुट जाएंगे। जिला कार्यकारिणी द्वारा हड़ताल समाप्ति की घोषणा करते हुए सीएमओ ड क्टर शैलेंद्र भटनागर को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है समस्त जिला कार्यकारिणी कुछ ही देर में उनसे मुलाकात कर समर्थन और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करेंगी।

लखनऊ में पांच जनवरी तक बढ़ी धारा १४४

राकेश पाण्डेय ''निश्छल''

लखनऊ। क्रिसमस पर्व, ३१ दिसंबर और नए साल पर पार्टी मनाने के दौरान कोविड प्रोटाकल का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का भी कड़ाई से लोगों को पालन करना होगा। जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत धारा १४४ कमिश्नरेट में पांच जनवरी २०२२ तक लागू रहेगी।इस दौरान विधानभवन और उसके आस पास एक किमी के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी। एक किमी की परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी। इंटरनेट मीडिया पर अफवाहे फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला बदर अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। मोहनलालगंज पुलिस एक जिला बदर अभियुक्त को आदेश का उल्लंघन करने पर जिले की सीमा में रहने पर किया गिरफ्तार पुलिस से प्राप्त जानकारी

के मुताबिक मोहनलालगंज पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र मनोहर लाल निवासी ग्राम बक्खा खेड़ा मजरा मऊ थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को पुलिस आयुक्त लखनऊ के द्वारा ६ अक्टूबर के आदेश के क्रम में ६ माह के लिए जिला बदर किया गया था किंतु अभियुक्त के द्वारा पुलिस से लुक छुप कर अपने गांव एवं रिश्तेदारी में जिले के अंदर निवास कर रहा था पुलिस को अभियुक्त के द्वारा अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने की सुचना मिली थी पुलिस ने अभियुक्त को मऊ मोड़ कस्बा मोहनलालगंज से सोमवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर मोहनलालगंज कोतवाली लेकर आई अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है

अपहरण की गई लडकी को किया बरामद

गोला खीरी। गोला कोतवाली के अंतर्गत प्रांशी गुप्ता पुत्री अनिल गुप्ता निवासी खुटार रोड विगत वर्ष २०२०, को मुकदमा अपराध संख्या ३६३ ६३६६ आईपीसी के तहत अज्ञात युवकों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा गोला कोतवाली मे दर्ज कराया गया था। मालूम हो कि खुटार रोड गोला निवासी अनिल गुप्ता ने गोला कोतवाली में अपनी पुत्री के अपहरण के तहत वर्ष २०२०,मे मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी लड़की विद्यालय जाते समय कहीं रास्ते से गायब हो गई है। जिसके चलते वर्तमान चौकी इंचार्ज खुटार रोड केके यादव, ने मुखबिर की सूचना पर गोला बस स्ट प से उस लड़की प्रांशी को बरामद कर लिया है। चौकी इंचार्ज के के यादव ने बताया कि लड़की लखनऊ भागने की फिराक मे थी और वह वर्तमान समय में लखनऊ में किसी मोहल्ले में रह रही है और उसने अपनी शादी मनमर्जी से किसी व्यक्ति के साथ कर ली है तथा उसको न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

फांसी के फंदे पर लटक युवक ने गंवाई जान

लखनऊ। कृष्णा नगर कोतवाली इलाके में किराए के मकान में रह रहे युवक ने रात घर में लगे पंखे के हुक में अंगोछा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मकान मालिक की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मृतक युवक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कृष्णा नगर कोतवाली प्रभारी आलोक राय ने बताया कि मूल रूप से दतवाली सम्भल का रहने वाला मृतक युवक सोनपाल ३२ पुत्र इंद्रपाल विगत एक वर्ष से मकान संख्या एल दितीए ७ में गिरजाशंकर के मकान में रह रहा था।

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने अपनाया हिंदू धर्म, रखा ये नया नाम

लखनऊ। इस्लाम धर्म के प्रति विवादित बयानों में रहने वाले सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सोमवार को सनातन ध र्म अपना लिया है। वसीम रिजवी अब हरबीर नारायण सिंह त्यागी हो गए हैं। गाजियाबाद में स्थित डासना देवी मंदिर में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरि ने रिजवी को पूजा–पाठ के साथ हिन्दू धर्म में शामिल किया है। इस्लाम छोड़कर हिन्दू बनने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी (वसीम रिजवी) ने कहा, "धर्म परिवर्तन की यहां कोई बात नहीं है, जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती हैं, और किसी धर्म में नहीं है. इस्लाम को हम धर्म ही नहीं समझते। हर जुमे की नमाज

के बाद हमारा सिर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमको कोई मुसलमान कहे, इससे हमको खुद शर्म आती है।" शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने पहले ही ऐलान किया था कि वह इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि डासना की देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती उन्हें सनातन धर्म में शामिल करवाएंगे। इस दौरान यति नरसिंहानंद ने कहा कि वसीम रिजवी ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक किताब लिखी है उसका विमोचन होना है। रिजवी से बात करके उन्हें अच्छा लगा और तब वह जान पाए कि वसीम कितने मानवतावादी और दिलेर व्यक्ति हैं। हिंदुओं को चाहिए तन, मन और धन से वसीम रिजवी का साथ दें। हम रिजवी के इस फैसले का समर्थन करते है और उनको हिन्दू धर्म में स्वीकार करते है। पूजा–पाठ के साथ वसीम रिजवी ने हिन्दू धर्म स्वीकार किया है।

नगर निगम के अफसर न्यायालय के आदेश को भी नहीं मानते

लखनऊ। नगर निगम के अफसर न्यायालय के आदेश को भी नहीं मानते हैं। शासन के आदेश पर नगर निगम में नियमित किए गए कर्मचारियों को अधिकारियों ने मनमानी कर हटा दिया है। यह बातें नगर निगम में बरसों से संविदा पर कार्यरत व हाल ही में हटाए गए २१ कर्मचारियों ने मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान कही है। सोमवार को मार्ग प्रकाश विभाग में संविदा पर कार्यरत लगभग ६५ संविदा कर्मचारी नगर आयुक्त को ज्ञापन देने नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे। कर्मचारियों का कहना है कि १९६७ से नगर निगम में संविदा पर कार्य कर रहे हैं। वेतन भी उन्हें सीधे नगर निगम से मिल रहा है। संविदा कर्मचारी हसन जिया ने बताया कि २०१२, २०१६ और २०१८ में हमें नगर निगम ने निकाल दिया था। हर बार हम लोग कोर्ट के आदेश पर वापस काम पर आ गए। २०१८ में कोर्ट के आदेश पर नियमित करने का आदेश ले आए, लेकिन कहा गया कि पद नहीं हैं। इसके बाद २०२० में भी नया आदेश लाने के बाद भी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं।

जैकलीन फर्नांडीज को ईडी ने हिरासत में लिया

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को मुंबई एयरपोर्ट पर रविवार को ईडी ने हिरासत में ले लिया था। जैकलीन शो के लिए विदेश जा रहीं थीं। लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा लुक आउट नोटिस जारी किए जाने के बाद उन्हें विदेश जाने से रोका

गया था। बता दें कि, जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ यह लुक आउट नोटिस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जारी किया गया था। जानकारी में सामने आया है कि, ईडी उनके खिलाफ जल्द ही नया समन जारी करेगी। आपको बता दें कि, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। इस मामले में ईडी की टीम उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। हाल ही के दिनों में एक्ट्रेस जैकलीन ने ईडी के समक्ष अपना बयान भी दर्ज करवाया था। जैकलीन फर्नांडिस का बयान सुकेश चंद्रशेखर के २०० करोड़ वसूली मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। बता दें कि, मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते ईडी ने जैकलीन के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया हुआ था, जिसके अनुसार वह मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लेकिन जब वह रविवार को मुंबई से विदेश जाने की फिराक में थीं, तब एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें रोक लिया। जैकलीन को इस मामले में एक गवाह के तौर पर माना जा रहा है और एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन के बीच कोई वित्तीय लेनदेन तो नहीं हुआ। आपको बता दें कि, सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जबरन वसूली के २० से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सुकेश एक ऐसा ठग है जिसने दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद होने के बावजूद एक कारोबारी से एक साल के अंदर २०० करोड़ रुपये की वसूली कर ली। उस पर जेल में से ठगी करने के आरोप हैं। उसने जेल के अंदर से ही एक रैकेट संचालित किया हुआ है। ईडी इसी की जांच में मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन से पूछताछ में लगी है।

यूपी में सभी विद्युत वितरण खंडों का होगा टेक्निकल ऑडिट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विद्युत वितरण खंडों की टेक्निकल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को बिजली अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कहा कि उपभोक्ता सेवाओं में कमियों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। जिनके निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने यूपीपीसीएल अध्यक्ष को निर्देश दिये कि 'सही बिल–समय पर बिल' उपभोक्ता को मिले, जिससे वे समय पर अपने बिलों का भुगतान कर सकें। साथ ही एकमुश्त समाधान योजना का भी अधिक से अधिक लाभ ले सकें। शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी लाभार्थी उपभोक्ताओं को इससे जोड़ने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता हित में योजना की तिथि १५ दिसंबर तक बढ़ाई है। इसलिए सभी लाभार्थी उपभोक्ताओं को इससे जोड़ने के लिए अधिकारी लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें। डिवीजन्स में ई–रिक्शा के माध्यम से योजना का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें। उन्होंने अस्थाई विद्युत कनेक्शन्स की भी जांच करने को कहा है। उन्होंने कहा कि टेम्परारी कनेक्शन्स देने में अनियमितता की शिकायतें आई हैं। ऐसे में इसकी जांच कराकर अनियमितताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये और नियमों के अधीन उन्हें स्थायी किया जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हित में बिलिंग एजेंसियों से हुए करार का शत प्रतिशत अनुपालन हो, प्रतिदिन के लक्ष्यों की समीक्षा हो। लापरवाही पर एजेंसी व डिस्क म दोनों की जवाबदेही तय की जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को रीडिंग के अनुसार बिल प्राप्त हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि डिवीजनवार हर जिले की बिलिंग की रोजाना समीक्षा की जाए। वीडियो कांफ्रेंसिंग में यूपीपीसीएल अध्यक्ष एम देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार के साथ सभी डिस्कॉम्स के एमडी व डायरेक्टर्स शामिल हुए।

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का एयरपोर्ट लुक हुआ वायरल

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर विक्कीकौशल और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की शादी की चर्चा पिछले कुछ दिनों से खूब हो रही है. अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दोनों राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं. विक्की कौशल और कैटरीना कैफ दोनों को ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया में शादी की जोर शोर से चर्चा है. विक्की कौशल एयरपोर्ट पर काफी खुश दिखाई दिए और लोगों को मुस्कुराकर रिसपोंड करते नजर आए. वहीं कटरीना कैफ अपनी मां के साथ एयरपोर्ट पर देखी गई और अपने लहंगे में वह काफी खूबसूरत नजर आ रही थी.विक्की कौशल ने एयरपोर्ट पर अपने प्रशंसकों का हाथ दिखाते हुए अभिवादन स्वीकार किया. विक्की कौशल इस दौरान प्रिंटेड शर्ट और बेज कलर की पैंट में दिखाई दिए. वहीं कटरीना कैफ अपने ट्रेडिशनल लुक के साथ राजस्थान के लिए रवाना हुई. कैटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं. कैटरीना भी येलो कलर के लहंगे में कमाल की खूबसूरत नजर आ रही थी. कैटरीना कैफ को एयरपोर्ट पर उनकी मां के साथ स्पॉट किया गया.कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी ६ दिसंबर को होनी है. शादी के

लिए मेहमान भी राजस्थान पहुंचने लगे हैं. कैटरीना कैफ की बहन ने और भाई शादी के लिए पहले ही जयपुर पहुंच चुके हैं. हालांकि अभी भी कई मेहमान ऐसे हैं जो नहीं पहुंचे हैं और उम्मीद है कि वे शादी के दिन ही पहुंचेंगे. इस दोनों स्टार कपल की शादी ६ दिसंबर को तय है. मेहमानों की इंट्री के लिए सिकरेट कोर्ड दिए गए हैं और फोटो लेने तक पर बांदी लगा दी गई है.

हमारे अन्य प्रतिनिधि

lat; ckt ib

lhrkiqj

ek-9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

lq'khy ukjk;.k feJ

क्षेत्रीय सम्पादक

lkjHk dqekj] fcgkj

ek-09386075289

मो० अरशद

C;wjk phQ

eऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा साई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।

आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar@yahoo.in adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक